लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 368
दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा बुनकर

368. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार को हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और अन्य संगठनों से अधिक रियायतें देने हेतु राज्य-वार कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और आज की तिथि के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) वर्तमान में हथकरघा बुनकरों को दी जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के कितने हथकरघा बुनकरों को अब तक इन रियायतों का लाभ मिला है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): वस्त्र मंत्रालय, पूरे देश में हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों सहित हथकरघा संगठनों/बुनकरों को विभिन्न रियायतें, लाभ और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

2. कच्चा माल आपूर्ति योजना

उपरोक्त योजनाओं के तहत, कच्चे माल, उन्नत करघों और सहायक उपकरणों, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड के निर्माण, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहायता, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता/रियायतें प्रदान की जाती हैं।

पिछले 5 वर्षों में, वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय ने देश भर में हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए 356 स्मॉल और 2 मेगा हैंडलूम क्लस्टरों को मंजूरी दी है, 880 मार्केटिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया है, 42,895 मुद्रा ऋण स्वीकृत किए हैं, 5,34,162 बुनकरों को पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई के तहत नामांकित किया है, और 163 उत्पादक कंपनियां बनाई हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र की योजनाओं के तहत पिछड़े क्षेत्रों के लाभान्वित हथकरघा बुनकरों सहित राज्य-वार हथकरघा बुनकरों की संख्या से संबंधित ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 02-12-2025 को लोक सभा के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 368 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र की योजनाओं के तहत लाभान्वित पिछड़े क्षेत्रों के हथकरघा बुनकरों सहित राज्य-वार हथकरघा बुनकरों की संख्या।

क्र.सं.	राज्य	लाभान्वित बुनकर
1.	आंध्र प्रदेश	85,201
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,356
3.	असम	46,120
4.	बिहार	5,968
5.	छत्तीसगढ़	7,509
6.	दिल्ली	172
7.	गोवा	27
8.	गुजरात	3,192
9.	हरियाणा	3,514
10.	हिमाचल प्रदेश	2,319
11.	जम्मू और कश्मीर	4,551
12.	झारखंड	5,713
13.	कर्नाटक	25,440
14.	केरल	17,140
15.	मध्य प्रदेश	4,657
16.	महाराष्ट्र	4,515
17.	मणिपुर	30,009
18.	मेघालय	494
19.	मिजोरम	2,617
20.	नागालैंड	1,073
21.	ओडिशा	34,538
22.	पुदुचेरी	1,520
23.	पंजाब	567
24.	राजस्थान	1,465
25.	सिक्किम	81
26.	तमिलनाडु	1,25,463
27.	तेलंगाना	44,871
28.	त्रिपुरा	1,749
29.	उत्तर प्रदेश	1,20,818
30.	उत्तराखंड	5,302
31.	पश्चिम बंगाल	55,964
32.	अखिल भारतीय (गैर-राज्य विशेष)	1,060
	कुल	**6,44,985**

*****